States have also been requested to undertake a detailed review of the existing arrangements, identify the deficiencies and plan the location of fair price shops so that the Public Distribution System becomes an effective instrument of poverty alleviation programme. The State Governments have also been advised to set up the Vigilance/Surveillance Committees consisting of voluntary agencies, leading personalities and women for getting sustained vigil over the working of fair price shops. It has been suggested to the State Governments to draw a plan of action for streamlining and strengthening the public Distribution System specially in the rural, tribal, hilly and inaccessible areas and to implement it within a time bound schedule.

कैलाश नगर और गांधी नगर, दिल्ली में विकास प्रभार

2440. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली 32 के निवासियों से पानी का कनेक्शन लगवाते समय 11 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से विकास प्रभार वसूल किया गया था और अब हर महीने उन्हें पानी का बिल जमा कराना पड़ता है तथा उसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम ने प्रति वर्ष उनसे सम्पत्ति कर के साथ-साथ जल कर वसूल करना भी आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जल-कर लगाने के क्या कारण हैं ,जबकि पानी का कनेक्शन देते समय विकास प्रभार पहले ही वसूल किया जा रहा है और मकान मालिक मासिक बिलों का भुगतान भी कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार संबंधित विभाग को उपर्युक्त निवासियों से जल-कर वसूल करने का आदेश देने का विचार रखती है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मुख्य पानी की लाइनें बिछाने के लिए प्लाटिड क्षेत्र के 10.67 रुपये प्रति वर्गगज की दर से विकास प्रभार तथा यदि परिसरों में मीटर लगाया जाता है तो मीटर का किराया सहित पानी की खपत के लिए पानी के प्रभार इन क्षेत्रों के निवासियों से वसूल किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति ने पानी का कनैक्शन नहीं लिया है, तो संपत्ति कर के बिलों के साथ-साथ जल-कर वसूल किया जाता है ।

(ख) पानी की खपत के लिए जल-कर (या पानी प्रभार) वसूला जाता है जबकि विकास प्रभार मूलभूत सुविधाओं के लिए है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्व श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार

2441. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार न दिए जाने के क्या कारण हैं जिसकी योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई थी और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यह योजना जारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि परिषद् को कोई अपना मन-माना व्यक्ति नहीं मिल रहा है और इस कारण जिन अध्यापकों को यह पुरस्कार मिलना था उनको यह पुरस्कार नहीं मिल रहा है तथा इसके लिए स्वीकृत 92 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में किसी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) हांलाकि "सर्व श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार" योजना एक विशिष्ट योजना के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान बनाई गई थी किन्तु नये पदों के सृजन

पर रोक के कारण इस योजना के परिचालन के लिए मानवशक्ति प्रदान नहीं की जा सकी। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की 7 वीं योजना में इस योजना को शामिल किया गया है और इस योजना के दौरान इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि परिषद को अपना मनोनुकूल व्यक्ति नहीं मिल रहा है और इस कारण जिन अध्यापकों को यह पुरस्कार मिलना था उनको पिछले कई वर्षों से यह पुरस्कार नहीं मिल रहा है। छठी योजना के दौरान इस योजना पर केवल 20 लाख रु० खर्च किये जाने थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

राज्यों को खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का आवंटन

2442. श्री केशव प्रसाद शुक्ल : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न और तेल आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में इस वर्ष हुई अनियमित वर्षा के कारण धान की फसल के क्षतिग्रस्त होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने चावल का अतिरिक्त आवंटन किए जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग की गई है और क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार की मांग को पूरा करने जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल के आवंटन स्टाक की समूची उपलब्धता सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल के आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) जी नहीं, अभी तक कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आवंटित किये गये चावल, गेहूं और खाद्य तेलों की मात्रा का ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित मात्रा		
		चावल	गेहूं	खाद्य तेल*
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश . . .	1075.0	189.0	75.5
2	असम . . .	410.0	327.6	1.6